देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/PALM/01

E-Newsletter, Issued in Public Interest

बुधवार, 3 अप्रैल 2019

ओवररेट पर निगरानी के लिए डकैतों को चोरों की पहरेदारी सौंप रखी है आबकारी विभाग ने

ओवररेट को इंस्पेक्टरराज की शह

जितना इंस्पेक्टरराज आबकारी विभाग में है उतना तो शायद पुलिस विभाग में भी नहीं है|यही कारण है कि इस विभाग में भ्रष्ट अधिकारीयों और लालची ठेकेदारों के नापाक गठजोड़ का इतिहास बरसो से चला आ रहा है और भविष्य में भी इस गठजोड़ के टूटने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही|यह गठजोड़ राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाले आबकारी विभाग से जुड़ा होने के कारण राज्य के सबसे संगठित माफियाओं में से एक है|पहले तो इनकी दबंगई इतनी थी कि यह पुलिस की तरह रेड पार्टी तक चलाती थी,जो राज्य में अपहरण,फिरौती,लूटपाट के लिए बदनाम थी|परन्तु धीरे धीरे सरकारों ने इनका प्रभाव ख़त्म करते हुए इन्हें हाशिये पर ला दिया|परन्तु समय के साथ भ्रष्ट अधिकारियों से मिलीभगत के चलते इस माफिया ने फिर सर उठा लिया है|

इस शराब माफिया का नया कारनामा है ओवररेट पर वसूली और इसके बदले विभाग को मिलने वाली हर महीने की फिक्स बंधी|यह ओवररेट वसूली जाती है बेबस जनता से, और पहुचाई जाती है, विभाग के हर छोटे से बड़े अधिकारी की जेब में,जिसे पहुचाने का काम करता है ठेकेदारों का एक संगठित " सिंडीकेट"|

इस " सिंडिकेट" का नियंत्रण राज्य के बड़े शराब माफिया के हाथो में है,जिन्होंने शहर में फैली शराब की दुकानों से वसूली के लिए अपनी ज़ोन स्तर पर ब्रांचे तक खोल रखी है|

सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, ओवर रेट की लूट चालू है!

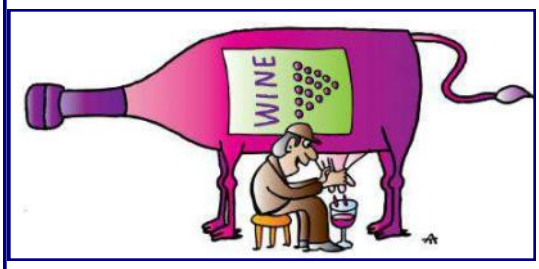

पिछली सरकार में ओवर रेट से ठेकेदारों को होने वाली 200 करोड़ की अतिरिक्त आय का खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया था,जिसके लिए हर दुकानदार द्वारा हर महीने दी जाने वाली बंदी,जो कि 8 से 10 हजार के बीच थी,के अतिरिक्त 15 से 25 हजार देने पर, हर बोटल पर 10 से पचास रूपये अतिरिक्त लेने की छूट शराब के ठेकेदारों को मिली थी|इस लूट से ठेकेदारों को 2-3 लाख हर महीने का अतिरिक्त फायदा हो रहा है और अधिकारीयों को मासिक बंधी में अधिक कमाई|गौरतलब है कि शहर की हर शराब की दूकान से बंधी का कलेक्शन शहर के एक बड़े तथाकथित ठेकेदार द्वारा की जा रही है|

यह लूट पिछली भाजपा सरकार से चालू हुई थी जो वर्तमान गहलोत सरकार में भी बिना किसी भय के निरंतर चालू है|

बेचारा खरीददार !!शराब के ठेकेदारों की गुंडागर्दी और लूटमार के सामने विवश

ओवररेट के नाम पर होने वाली इस खुली लूट का आसान और अंतिम शिकार तो आखिरकार ग्राहक को ही होना है|हर दिन किसी ख़ुशी या गम में पीने वाला ग्राहक जब दूकान पर चढ़ता है तो इस ओवररेट के कारण खुन का घूंट पीकर,बोझिल मन से इस निश्चय के साथ उतरता है कि वह इस मामले की शिकायत विभाग के उच्च अधिकारियों से करेगा|पहले तो उसे विभाग के शिकायत कक्ष का नंबर नहीं मिलता और जब मिलता भी है तो कोई उस पर जवाब नहीं देता|थकहार कर वह अपने खुन पसीने की कमाई से खरीदी हुई ओवररेट की शराब को पीकर,विभाग को कोसता हुआ सो जाता है|कुछ विरले हिम्मत कर लिखित शिकायत करते है तो उन शिकायतों पर विभाग क्या कार्यवाही करता है इसका उदाहरण इस रिपोर्ट में आगे पढ़ते है|

ओवररेट पर ओवररेट का खेल

गौरतलब है कि ओवररेट के चलते शराब ठेकेदारों ने प्रति बोटल 10

से 50 रुपये बढाए है परन्तु वास्तव में इन शराब की दुकानों को ,दूकान के सेल्समेन चलाते है जिन्होंने प्रति बोटल अपने 10 रूपये अलग से जोड़ रखे है|मतलब यदि एक बोटल पर प्रिंट रेट 89 रूपये है तो शराब की दूकान का सेल्समेन बोटल पर प्रिंट एम.आर.पी. को भी राउंड फिगर में पूरा ले कर,उस पर ठेकेदार के 10 रूपये और स्वयं के 10 रूपये जोडकर कुल 120 रूपये ले लेता है|इसके अलावा ग्राहक की शक्ल और उसके पहले से शराब के नशे में होने की परिस्थिति को देखकर भी मनमानी वसूली कर लेता है|

मुख्यमंत्री की 8 बजे की सख्ती और साल दर साल बढती सरकारी फीस है,इसका कारण

चूँकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर सख्ती के चलते शराब ठेकेदारों की रात 8 बजे बाद होने वाली काली कमाई मारी जा रही है साथ ही आबकारी विभाग साल दर साल एक्साइज फीस भी मनमाने ढंग से बढाता जा रहा है,इसलिए शराब ठेकेदारों के पास ओवररेट ही वसूली का एकमात्र जरिया बन गया है|

आबकारी विभाग जयपुर शहर पश्चिम में हुई ओवररेट की शिकायत पर विभाग की फेब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंसी /कार्यवाही का नमूना देखिये|

दिनांक 17/03/2019 को एक शराब क्रेता द्वारा खातीपुरा रोड पर एक अंग्रेजी शराब के ठेके से बियर क्रय की परन्तु ठेकेदार द्वारा

ओवररेट के नाम पर तीन बियरों के 153 रूपये अतिरिक्त ले लिए गए,तकाजा करने पर ठेकेदार ने गालीगलोच कर उसे वहा से भगा दिया,जब इस मामले की शिकायत आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा से करनी चाही तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया|जिस पर एक लिखित शिकायत अगले दिन जिला आबकारी अधिकारी श्रीमति रेखा माथुर को की गयी|जिन्होंने इस शिकायत पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया|

परन्तु दिनांक 28/03/2019 को आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा ने इस प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए बताया कि उनके द्वारा एक बोगस ग्राहक से इस दूकान पर बियर की खरीद करवाई गयी और शराब ठेकेदार ने प्रिंट रेट पर ही बियर को बेचा है अतः शिकायत निराधार है|

दोहराई जाती है यही कहानी:अमूमन यही कहानी आबकारी विभाग में ओवररेट की शिकायत करने वाले हर लाचार ग्राहक के साथ दोहराई जाती है|नतीजन वह विभाग से शिकायत करना ही छोड़ देता है|

बड़ा सवाल-1

क्यों डीईओ रेखा माथुर ने बिल्ली को दूध की रखवाली दे रखी है?

शिकायतकर्ता से बातचीत में स्वयं डीईओ रेखा माथुर ने यह माना था कि ओवररेट एक बड़ी समस्या है और विभाग इस पर क्रॉस चेक करेगा|तो क्यों उनके द्वारा उसी ज़ोन के निरीक्षक से,जो कि अपने ज़ोन की हर शराब की दूकान से उनके खिलाफ आने वाली शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए 10000 से 35000 रूपये प्रोटक्शन मनी के नामपर रिश्वत में लेती है,को इस मामले की जांच सौपी?

बड़ा सवाल-2

क्यों शिकायतकर्ता की संतुष्टी के लिए उसके सामने दुबारा शराब की खरीद नहीं करवाई गयी?

जब ग्राहक द्वारा स्वयं इस मामले की शिकायत डीईओ स्तर पर की गयी थी तो क्यों आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा द्वारा ग्राहक कीसंतुष्टी के लिए उससे या उसके सामने बियर की खरीद नहीं करवाई गयी?क्यों आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा द्वारा फेब्रिकेटेड ट्रांसपेरेंसी प्रदर्शित करते हुए मामले में

स्वयं और अपने विश्वस्त संविदा गार्ड मांगीलाल को इस जाँच में शामिल रखा?

आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा की कार्यप्रणाली पर उठ चुकी है उँगलिया,मांगीलाल है ठेकेदारों का मुखबिर|

जहाँ तक आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा और संविदा गार्ड मांगी लाल के गठजोड़ की बात है तो यह दोनों लम्बे समय से इस विभाग में साथ कार्य कर रहे है,मांगीलाल जो इसी विभाग से पिछले साल ही सेवानिवर्त हुआ है,आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा का दायाँ हाथ होने की वजह से, रिटायर्ड होने के बावजूद, संविदा पर पुनः आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा के पास अपनी ड्यूटी बजा रहा है|उसे जयपुर शहर का हर ठेकेदार जानता है और उसे नजराना भेंट करता है बदले में मांगीलाल विभाग द्वारा की जाने वाली संभावित कार्यवाही/रेड/गश्त की सूचना ठेकेदार को अग्रिम दे देता है जिससे ठेकेदार समय से सावधान हो जाता है और ग्राहकों से की जाने वाली वसूली/

लूटखसोट को बंद कर शरीफ गाय बन जाता है|और ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह तो बचपन से,नितांत शरिफायी से शराब का व्यवसाय कर रहा है और उससे ज्यादा मासूम,शरीफ और ईमानदार ठेकेदार पूरी दुनिया में नहीं है|

पिछले साल जांच में फंसने पर इसी आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा को बचाने के लिए आबकारी विभाग को दो दुकानों की लोकेशन बदलनी पड़ी थी|जिसका गवाह पूरा आबकारी विभाग है|

ईमानदारी के साथ भी जमीर मर चुका है इस विभाग में

राज्य में शराब का सेवन करने वालों की संख्या लाखों में है जिनसे रोज यह शराब ठेकेदार बिना किसी डर के खुलेआम लूटखसोट करते है|,विभाग के छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी भी ठेकेदारों के इस खेल में शामिल होकर दिन-रात भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है|इससे प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों में ईमानदारी के साथ जमीर भी दम तोड़ चुका है|

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग लगातार कर रहा है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही

पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने आबकारी विभाग के कई आला अधिकारियों को घुस लेते रंगे हाथों पकड़ा है,इसी 28/03/2019 को हनुमानगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को 1.38 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया|ऐसे में लगता है जयपुर के भ्रष्ट अधिकारियों के पाप का घड़ा भी भर चुका है और किसी भी समय फुट सकता है|

यदि एक दूकान पर भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कार्यवाही करे,तो रुक सकती है ग्राहकों से लूटखसोट

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग यदि किसी एक दूकान पर भी हाथ डाल देवें तो यकीनन पुरे शहर में ग्राहकों से होने वाली लूटखसोट थम जाएगी|इसी भरोसे, शहर के हजारों ग्राहक मन ही मन भगवान(दीनो के ईश)से इन लूट के अड्डों पर बड़ी कार्यवाही की उम्मीद लगाए बैठे है,देखना यह है कि भगवान् की लाठी जिसमे आवाज नहीं आती,कब चलती है|

एसीबी की कार्रवाई • ठेके की लोकेशन पास करने के वसूल रहे थे ₹5 से 10 हजार

जिला आबकारी अधिकारी, बाबू और सूचना सहायक से ₹1.38 लाख बरामद

भास्कर न्यूज | हनुमानगढ़

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर की टीम ने गुरुवार को जिला आबकारी अधिकारी, बाबू और सूचना सहायक के कब्जे से एक लाख 38 हजार तीन सौ रुपए की रिश्वत रकम जब्त की। यह रिश्वत रकम नए वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित शराब दुकानों की लोकेशन पास करने की एवज में वसूली गई। एक दुकान की लोकेशन पास करने के लिए पांच से दस हजार रुपए तक की रिश्वत बटोरी जा रही थी। खास बात है कि यह कार्रवाई एसीबी ने महज सूचना के आधार पर की। इस कार्रवाई को लेकर एसीबी को किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं मिली थी। हैरानी की बात है कि रिश्वत रकम सहित गिरफ्त में आए बाबू की अलमारी से तीन अलग-अलग ब्रांड की शराब की 21 बोतलें भी मिलीं। इसके लिए एसीबी की ओर से बाबू के खिलाफ अलग से आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल इस मामले में बाबू कुलदीप को कार्यालय की अलमारी में अवैध तरीके से शराब रखने के मामले

एसीबी की गिरफ्त में रिश्वत के आरोपी

में गिरफ्तार किया गया है। सीकर एसीबी के डिप्टी एसपी कमलप्रसाद ने बताया कि ब्यूरो को शिकायत मिली कि हनुमानगढ़ में वर्ष 2019-20 की लॉटरी में आवंटित शराब दुकानों की लोकेशन पास करने की एवज में आबकारी विभाग में पांच से दस हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने यहां पहुंचकर कार्रवाई की तो जिला आबकारी अधिकारी सहदेव सिंह रत्नू की जेब से 30 हजार रुपए एवं वरिष्ठ लिपिक कुलदीप छींपा (40) की जेब में 95 हजार रुपए मिले। वहीं सूचना सहायक सीमा मोदी (42) के बैग से 6300 रुपए मिले वहीं उसकी पेंट की जेब से सात हजार रुपए मिले।

एक साल बाद दूसरी कार्रवाई

गत 20 मार्च 2018 को एसीबी की बीकानेर टीम ने हनुमानगढ़ आबकारी थाना के प्रहराधिकारी हुक्मसिंह मीणा और उसके ड्राइवर हरबंशलाल को छह हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत गांव अयालकी में आवंटित शराब दुकान को सुचारू रूप से संचालित करने की एवज में तीन हजार रुपए मंथली के हिसाब से ली गई थी। घूस की राशि सहित पकड़े गए। इधर, एसीबी टीम ने गिरफ्त में आए अधिकारी और कर्मचारियों के घर की भी तलाशी ली। टीम की ओर से दोनों के बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे।

इधर, अजमेर में एलडीसी 15 हजार की घूस लेते पकड़ा

मदनगंज-किशनगढ़ (अजमेर) | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने गुरुवार को नगर परिषद में कनिष्ठ लिपिक को मकान के पट्टे जारी करने के नाम पर 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एसीबी ने उसके कमरे से ही दबोच लिया। राजस्व शाखा के एलडीसी मोहनलाल पाराशर (30) ने परिवादी से पट्टा जारी कराने के नाम पर 20 हजार की मांग की। सौदा 15 हजार में तय हुआ और आरोपी पकड़ लिया गया।

₹400 की रिश्वत लेते वरिष्ठ कार्यालय सहायक गिरफ्तार

गंगापुर सिटी | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर की टीम ने शुक्रवार को प्रहलाद कुमार मीना वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप तहसील बरनाला (बामनवास) को 400 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। प्रहलाद कुमार ने यह राशि किसान क्रेडिट कार्ड के फॉर्म पंजीयन व जल्दी देने के एवज में मांगी थी।

राजस्थान पत्रिका द्वारा चलायी गयी मुहीम

चुनावी साल : यूपी की तर्ज पर शराब ठेकेदारों से 'वसूली'

मय पर 'मंथली', ओवर रेट पर बिक्री कहां जाएंगे 300 करोड़ रुपए

अंग्रेजी शराब और बीयर पर 10 से 15 रुपए की दी खुली छूट

देशी वालों की जेब पर ओवर रेट नहीं, दूसरे रास्ते से डाला भार

एक्सक्लूसिव

इस पूरे खेल पर आंखें बंद किए हुए है आबकारी विभाग

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. चुनावी साल शराब-बीयर के शौकीनों पर भारी पड़ेगा। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर प्रदेश के ठेकेदारों को चुनावी साल में 300 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य सौंपा गया है। इसकी आड़ में ठेकेदारों ने अंग्रेजी शराब और बीयर पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा वसूली शुरू कर दी है। इस पूरे खेल पर आबकारी विभाग ने आंख बंद कर ली है।

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार की टीम ने हर अंग्रेजी शराब की दुकान से 10 से 15 हजार रुपए की 'मंथली' लेना शुरू कर दिया है। ठेकेदारों के मुताबिक ओवर रेट की कैंची से रोज 1 से 1.25 करोड़ रुपए की प्रदेश में वसूली होगी। विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे। ऐसे में नवंबर तक 7 माह में अंग्रेजी शराब के ठेकेदारों को करीब 250 करोड़ रुपए की 'मंथली' वसूल कर सौंपनी है। बाकी 50 करोड़ देशी शराब ठेकेदारों से इस फंड में शामिल कर 300 करोड़ का लक्ष्य पूरा होगा। राज्य में अब सरपरस्ती में रोजाना करीब 15 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब-बीयर बिक रही है।

आंकड़ों से समझें वसूली गणित

- **1000** राज्य में अंग्रेजी शराब दुकान
- **10-15** हजार तक हर दुकान से होगी वसूली
- **1 से 1.25** करोड़ तक रोज होगी वसूली
- **250** करोड़ के करीब नवंबर तक ओवर रेट वसूली
- **50** करोड़ देशी शराब ठेकेदारों को भी देने होंगे

शराब से आय

- **8500** करोड़ का सालाना राजस्व सरकार को
- **6000** करोड़ अंग्रेजी शराब व बीयर से
- **2000** करोड़ देशी शराब से
- **500** करोड़ भांग व अन्य से

ओवर रेट लेने पर कार्रवाई की जा रही है। हाल ही कुछ शिकायतें आई थी, उन पर कार्रवाई की गई है।
राजेश वर्मा, जिला आबकारी अधिकारी जयपुर

यों सामने आया सच

एमआरपी से ज्यादा पैसा देकर शराब खरीदने वाले लोगों ने पत्रिका को बताया कि जब इस संबंध में शराब विक्रेताओं से पूछा तो उन्होंने बोला कि ओवर रेट का पैसा वह घर नहीं ले जाएंगे। यह पैसा चुनावों के लिए देना है।

रेट राउंड फिगर में

अंग्रेजी शराब व बीयर पर 10 से 20 रुपए तक अधिक वसूली हो रही है। कीमत को राउंड फिगर में कर दिया गया है। बीयर की एमआरपी 97 रुपए के आसपास है, पर इसके 110 से 120 रुपए तक लिए जा रहे हैं।

ग्राउंड जीरो

जवाहर नगर गोल मार्केट

506 रुपए की प्रिंट रेट वाली अंग्रेजी शराब की बोतल पर दुकानदार ने 525 रुपए मांगे। रिपोर्टर ने जब प्रिंट रेट ही देने की बात कही तो दुकानदार ने मना कर दिया।

गोविंद मार्ग

705 रुपए की प्रिंट रेट वाली अंग्रेजी शराब की बोतल पर दुकानदार ने 730 रुपए मांगे। रिपोर्टर ने जब प्रिंट रेट ही देने की बात कही तो दुकानदार ने मना कर दिया।

400 करोड़ का आंकलन कर चुका विभाग

आबकारी विभाग में पिछले दो-तीन वर्ष में नई आबकारी नीति पर विचार में भी अंग्रेजी शराब व बीयर की कीमत 10 से 15 रुपए तक वृद्धि पर 450 करोड़ से अधिक राजस्व बढ़ोतरी का आंकलन था। इस वर्ष सात माह में ओवर रेट वसूली से 250 करोड़ जमा होंगे।

उधर, आबकारी विभाग के अफसरों की शह पर ओवर रेट वसूली पर कार्रवाई की भी खानापूर्ति होगी। सूत्रों के मुताबिक मामूली केस व जुर्माना लेकर कार्रवाई हो सकती है। वैसे ओवर रेट वसूली पर जुर्माना या लाइसेंस निलंबन हो सकता है।

रात के आठ बजे बाद भी राहत

रात को शराब दुकान आठ बजे बंद करने के नियम हैं। पर इसमें 15 से 20 मिनट की राहत है। दुकान बंद होने के बाद दुकान के आसपास धड़ल्ले से बिक्री होती है। रात को तो ओवर रेट 100 रुपए तक ली जा रही है।

राजस्थान पत्रिका द्वारा चलायी गयी मुहीम

चुनावी साल में शराब ठेकेदारों, बीयर कम्पनियों पर नजर

दाम चढ़ाने के फेर में सप्लाई आधी

पत्रिका

एक्सक्लूसिव

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

जयपुर. चुनावी साल में शराब ठेकेदारों पर ही नहीं, बीयर कम्पनियों पर भी नजर है। दोनों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली का लक्ष्य है। इनमें से 300 करोड़ ठेकेदारों से और 200 करोड़ बीयर कम्पनियों से वसूलने की कोशिश चल रही है। ठेकेदार तो ओवर रेट पर शराब-बीयर बेचने की अघोषित मंजूरी के बाद 'सेवा शुल्क' देने को तैयार हो गए हैं लेकिन बीयर कम्पनियां फिलहाल तैयार नहीं हैं। नतीजतन बीयर के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है।

बीयर निर्माता कम्पनियों को कहा है कि दाम में बढ़ोत्तरी चाहिए तो 200 करोड़ रुपए 'सेवा शुल्क' देना होगा।

पढ़ें दाम @ पेज 12

सौदा हुआ तो ₹ 1,500 करोड़ ज्यादा निकलेंगे मयकशों की जेब से

अब बीयर कम्पनियों से 20 रुपए बढ़ाने के लिए मांगा 200 करोड़ रुपए 'सेवा शुल्क'

अंग्रेजी-देशी शराब में भी खेल

अंग्रेजी-देशी शराब की कीमत भी इसी तर्ज पर बढ़ती रही है लेकिन चुनावी साल में 'सेवा शुल्क' बढ़ गया है। अंग्रेजी शराब में प्रति बोतल और देशी शराब में प्रति पेटी कीमत बढ़ाई जाती है। देशी शराब में पेटी पर 20 रुपए कागजों में बढ़ाए जाते हैं जबकि वसूली 40 रुपए की होती है। सेवा शुल्क के रूप में 20 रुपए सीधे बिचौलियों को पहुंचाए जाते हैं।

घटाई आपूर्ति, बढ़ाई किल्लत

दाम बढ़ाने और जेबें भरने के फेर में बाजार में बीयर की कमी पैदा कर दी गई है। आरएसबीसीएल के गोदामों पर ठेकेदारों को मांग के मुकाबले आधी ही आपूर्ति की जा रही है। ठेकेदारों को तर्क दिया जा रहा है कि बीयर की लागत बढ़ गई इसलिए कम्पनी माल कम भेज रही है। कुछ बीयर कंपनियां बंद होने और पानी की कमी सहित अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं।

तस्करी बढ़ने का कारण

राजस्थान स्टेट बेवरीज कॉर्पोरेशन (आरएसबीसीएल) का गठन वर्ष 2005 में जिलों के ठेके एकसाथ उठने की व्यवस्था समाप्त होने के बाद किया गया था। सूत्रों की मानें तो तत्कालीन अधिकारियों ने तय किया था कि दिल्ली कॉर्पोरेशन, आर्मी केन्टीन या पड़ोसी राज्यों के समान ही शराब व बीयर खरीद के दाम तय किए जाएंगे। लेकिन कंपनियां सेवा शुल्क की आड़ में लगातार मनमर्जी से कीमतें बढ़वाती आ रही हैं। कीमतों में भारी अंतर के कारण शराब तस्करी को भी बढ़ावा मिलता है।

जयपुर शहर में इतनी है खपत

जानकारी के अनुसार अकेले जयपुर शहर में प्रत्येक शराब की दुकान पर रोजाना 30 से 40 पेटी बीयर की बिक्री हो रही है। वहीं राज्य में बीयर की सालाना करीब 2.5 करोड़ पेटी की खपत है। आंकड़ों की मानें तो बाजार में हर माह लगभग 21 लाख पेटी बीयर की मांग है। वहीं शौकीन लोग रोजाना लगभग 70 हजार पेटी बीयर पी रहे हैं।

आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में शराब के मुकाबले बीयर से राजस्व मिल रहा है। इसीलिए अब आबकारी विभाग में इसके दाम को लेकर उठापटक चल रही है।

मयकशों पर आएगा 1500 करोड़ का भार

बीयर की कीमत बढ़ी तो बिचौलियों के 'सेवा शुल्क' से कहीं ज्यादा राजस्व राज्य सरकार को मिलेगा। इसका सीधा असर शराब के शौकीनों यानी आखिरकार जनता पर ही होगा। मोटे अनुमान के मुताबिक अकेले बीयर महंगी होने से जनता पर 1500 करोड़ से अधिक का भार आएगा।

पेज 1 का शेष...

दाम...

कम्पनियां 125 करोड़ रुपए तक देने को राजी भी हो गई, मामला 200 करोड़ की जिद पर अटक गया है। ठेकेदारों ने भी कम्पनियों से बीयर की सप्लाई लेना आधा कर दिया है। वसूली का यह खेल राज्य में सक्रिय बिचौलियों की मदद से खेला जा रहा है।

राजस्थान पत्रिका द्वारा चलायी गयी मुहीम

होटल में जुटे थे 150 से ज्यादा ठेकेदार

26/05/18/RP

एक होटल में लिखी शराब-बीयर पर ओवर रेट वसूली की पटकथा!

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. चुनावी साल में शराब के शौकीनों की जेब काटने के शुरू हुए खेल को आबकारी विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ही पाला-पोसा जा रहा है। चुनाव में कुछ ही माह बचे है और इस दौरान जनता को कितना लूटा जा सकता है, इसी पर कसरत की जा रही है। शराब-बीयर पर ओवर रेट वसूली को लेकर जयपुर में एक होटल में ठेकेदारों ने विभागीय अधिकारियों से सलाह कर रणनीति तैयार की।

सूत्रों के मुताबिक सप्ताहभर पहले बनीपार्क स्थित एक होटल में हुई बैठक में 150 से ज्यादा शराब ठेकेदार मिले।

पढ़ें एक @ पेज 20

आबकारी अधिकारी ने ओवर रेट पर चालान नहीं करने की दी गारंटी

कागजी खानापूर्ति को लेकर चालान किया भी, तो यूनियन भरेगी जुर्माना

ओवरेट वसूली पर लाइसेंस निलंबन के वैधानिक प्रावधान का नहीं हो रहा पालन

बैठक में यह कहा गया

शराब ठेकेदारों के मुताबिक बैठक में कहा था कि ओवर रेट वसूली की एवज में प्रत्येक दुकान से 15 हजार रुपए हर माह वसूल किए जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर का नाम लेकर कहा कि उन्होंने ओवर रेट पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है। दुकान का कागजी रिकॉर्ड पूरा करने के लिए चालान किया भी तो उसकी जुर्माना राशि ठेकेदार यूनियन की ओर से भरी जाएगी।

दफ्तर में बैठ काट दिए चालान

ओवर रेट वसूली के खेल का राजस्थान पत्रिका ने 'मय पर मंथली, ओवर रेट पर बिक्री, कहां जाएंगे 300 करोड़' खबर प्रकाशित कर खुलासा किया था। इस पर कुछ दुकानों पर कागजी कार्रवाई की। शराब कारोबारियों के मुताबिक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही दुकानों के ओवर रेट के चालान बनाए गए।

दाम चढ़ाने के फेर में सप्लाई आधी

मय पर 'मंथली', ओवर रेट पर बिक्री कहां जाएंगे 300 करोड़ रुपए

राहत दल (एसडीआरएफ) एडीजी बी.एल. सोनी ने मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन लू की चेतावनी जारी की है। एडीजी ने बताया कि इस सम्बंध में सभी जिलों के एसपी को अलर्ट किया गया है।

एक... 26/05/18/RP

वहां किस शराब-बीयर ब्राण्ड पर तय कीमत से कितनी ज्यादा कीमत ली जाए, इस पर मंथन हुआ। ठेकेदारों ने यूनियन बनाकर और मनमर्जी से शराब कीमत बढ़ाकर ओवर रेट की सूची तैयार कर सभी दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा। सभी दुकानों पर नई सूची गुप्त रूप से पहुंचा दी गई है। इसमें 5 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। जिन ब्राण्डों की बाजार में डिमाण्ड ज्यादा है, उन पर ज्यादा ओवर रेट लागू की गई है। हर दुकान से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की वसूली को लेकर जोनवार ठेकेदारों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

शीर्ष कोर्ट...

जज का पद किसी की संपत्ति नहीं है जिसे जाति-धर्म पर बांटें : तिरुवनंतपुरम . केरल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीके पाशा ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, जज पद परिवारिक संपत्ति नहीं, जिसे जाति या धर्म के आधार पर बांटा जाए। यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट में जजों के खाली पद भरने के लिए कॉलेजियम द्वारा सुझाए नामों के बाद आई है। इन नामों की सिफारिश रद्द करने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जो खारिज हो गई। याचिकाकर्ता वकील सीजे जोवसन और साबू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दिए नामों को खारिज करने की मांग की थी।

सचिवालय से आए उच्चाधिकारी ने ली बैठक

ओवररेट की कमाई 2 से 3 लाख हर माह, सेवा सिर्फ 15 हजार

फिर भी दी ओवररेट वसूली को खुली छूट

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर . चुनावी वर्ष में शराब दुकानों पर तय कीमत से ज्यादा (ओवररेट) वसूली का सप्ताहभर पहले शुरू हुआ सिलसिला थम नहीं रहा। सिस्टम में शामिल नहीं होने वाले इक्का-दुक्का दुकानदारों को दूसरे शराब ठेकेदार जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर का नाम लेकर कार्रवाई कराने के लिए कहकर धमका रहे हैं।

ओवररेट वसूली के चलते हर शराब दुकान पर 10 से 15 हजार रुपए रोजाना की आय बढ़ गई है। जिन शराब दुकानों पर 1 लाख रुपए की रोजना शराब बिक्री हो रही थी। उनकी बिक्री अब 1.15 लाख तक पहुंच गई है। ऐसे में हर माह प्रत्येक दुकानदार को 2 से 3 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी। इस मामले में हाल ही सचिवालय से आए एक उच्चाधिकारी ने वित्त भवन में बैठक भी ली, लेकिन फिर भी ओवररेट मामले में खुली छूट दे दी। ऐसे में यह सिलसिला जयपुर सहित राज्यभर में तेज हो गया है।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर।

चुनाव आते ही 'सेवा'

प्रदेश में 5 माह बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में ठेकेदार 'सेवा' को लेकर उच्च स्तर से मिली हरी झण्डी के चलते कमाई में जुट गए हैं। पहले अक्सर शराब दुकान ठेकेदारों में एक-दूसरे के क्षेत्र में शराब बिक्री पर विवाद रहता था। लेकिन अब ओवररेट को लेकर बने पूल सिस्टम में ठेकेदार एक हो गए हैं। सूत्रों की मानें तो हर दुकानदार से उच्च स्तर पर सेवा करने के लिए ठेकेदार यूनियन प्रतिमाह 15 हजार रुपए वसूल कर रही है। जबकि हर दुकानदार की ओवररेट से आय 2 से 3 लाख रुपए बढ़ेगी।

हर माह 1.5 करोड़ सेवा शुल्क

प्रदेश में अकेले अंग्रेजी शराब की ही 1000 दुकानें हैं। हर दुकान से 15 हजार रुपए प्रति माह लिए जाएंगे। ऐसे में जिलों की शराब ठेकेदार यूनियनें सेवा शुल्क के लिए दुकानदारों से 1.5 करोड़ रुपए वसूल करेंगी। यह राशि उच्च स्तर पर जाएगी। जबकि इस ओवररेट वसूली का दूसरा पहलू देखा जाए तो हर माह 1.5 करोड़ रुपए सेवा शुल्क वसूली की आड़ में शराब ठेकेदार जनता से 200 करोड़ से ज्यादा वसूलेंगे। इस लूट से दुकानों पर शराब पीने वालों की कहासुनी हो रही है। अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं।

राजस्थान पत्रिका द्वारा चलायी गयी मुहीम

तेरह साल पहले खत्म शराब ठेकेदारों का गठजोड़ 'वसूली' के लिए फिर बना

सरकारी रेट सूची कचरे में, ठेकेदारों ने लागू की मनमर्जी की दर सूची

चुनावी साल नया खेल, ठेकेदार और उच्च स्तर पर सभी भर रहे जेबें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. 13 साल पहले राज्य में खत्म किए गए शराब माफिया के गठजोड़ को चुनावी साल में अधिकरियों ने अपनी जेबें भरने तथा उच्च स्तर पर सेवा के लिए फिर कायम कर दिया गया है। प्रदेश में ठेकेदारी सिस्टम के तहत जिलेवार ठेके देने के स्थान पर एक-एक शराब दुकान का लॉटरी से आवंटन शुरू हुआ था।

अधिकारियों की देखरेख में प्रदेशभर में शराब दुकानों पर 'ओवररेट' वसूली का खेल शुरू करा दिया गया है। 'राजस्थान पत्रिका' ने वास्तविकता की पड़ताल को लेकर शनिवार को राज्यभर में शराब दुकानों का स्टिंग कराया, तो हर जिले में ओवररेट वसूली का खेल मिला। बैखोफ शराब ठेकेदार मनचाही रेट वसूल रहे है।साथ ही जो ओवररेट वसूली का विरोध और शिकायत की बात करता है, उसे सेल्समेन खुली चुनौती दे रहे है। ऐसे वाकये जयपुर में सचिवालय सहित कई विभागों में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के साथ भी हो चुके है। राज्य में अंग्रेजी शराब-बीयर की 1000 दुकानें हैं। इन दुकानों पर रोज ओवररेट के खेल में जनता की जेब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की जा रही है। इसको लेकर जिला आबकारी कार्यालयों में शिकायत भी की जा रही है। इस पर अनजान लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है।

पढ़ें तेरह @ पेज 08
(सरकार नहीं शराब कारोबारी तय करते हैं कीमतें : देखें पत्रिका स्टिंग @ पेज 09)

यों समझे ओवर रेट वसूली का गणित

30 करोड़ की ओवररेट वसूली अंग्रेजी शराब और बीयर पर हर माह राज्य में

01 हजार अंग्रेजी शराब दुकानों पर रोज 1 करोड़ से ज्यादा की 'लूट'

10 हजार रु. की बढ़ोतरी हर शराब दुकान की आय में रोजाना

पत्रिका के पास ठेकेदारों की ओवररेट सूची

सरकारी शराब दर सूची को दरकिनार कर ठेकेदारों की ओर से लागू की गई ओवररेट की सूची पत्रिका के पास उपलब्ध है। यह शराब ठेकेदारों की यूनियन ने एक होटल में बैठकर तैयार करने के बाद सभी दुकानदारों को अधिक दर वसूली के लिए बांटी है।

शराब की दुकानों पर लूट का खेल : 15 से 25 फीसदी तक कीमतें ज्यादा कर रहे वसूली

सरकार नहीं, शराब कारोबारी तय करते हैं कीमतें

पत्रिका स्टिंग न्यूज

प्रदेश में लाइसेंसी शराब की दुकानों में किस तरह लूट का खेल चल रहा है, राजस्थान पत्रिका ने पूरे प्रदेश में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इसकी जमीनी हकीकत खंगाली। हैरान करने वाली बात है कि शराब कारोबारी किस कदर मन माफिक कीमतें उपभोक्तओं से वसूल रहे हैं। कई स्थानों पर 15 से 25 फीसदी तक ज्यादा कीमतें वसूली जा रही हैं। इतना ही नहीं कुछ जगह तो शराब कारोबारियों ने मिलकर खुद ही कीमतें तय कर लीं। देखिए किस तरह चल रहा है शराब की दुकानों पर लूट का खेल----

राजधानी में ही बिक रही है महंगी शराब

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. शहर में शराब की दुकानों पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। दुकानदान निर्धारित रेट से 20-25 रुपए ज्यादा दरों पर शराब बेच रहे हैं। आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण यह वसूली सिर्फ एक दुकान पर नहीं बल्कि शहर की लगभग हर शराब की दुकान पर चल रही है। पत्रिका टीम ने अलग-अलग दुकानों पर जाकर पड़ताल की।

गोविंद मार्ग

टीम नगर अपराह्न साढ़े तीन बजे गोविंद मार्ग स्थित मोतीडूंगरी थाना के पास शराब की दुकान पर गई। जहां एक ब्रांड की शराब की बोतल ली, जिस पर रेट 506 रुपए अंकित थी। लेकिन दुकानदार ने 525 रुपए मांगे। रिपोर्टर ने जब प्रिंट रेट ही देने की बात कही तो दुकानदार ने मना कर दिया।

जवाहर नगर

टीम इसके बाद चार बजे जवाहर नगर गोल मार्केट के पास स्थित शराब की दुकान पर गई। जहां पर एक ब्रांड की शराब की बोतल की मांग की। बोतल पर रेट 705 रुपए अंकित थी। लेकिन दुकानदार ने 730 रुपए की मांगे।

किस की क्या रेट

व्हिस्की प्रिंट	व्हिस्की बिक्री	बीयर प्रिंट	बीयर बिक्री
498	510	97	110
506	525	133	150
404	420	115	130
[illegible]	740	96	110

इन सभी स्टिंग के पत्रिका के पास वीडियो हैं

श्रीगंगानगर : प्रिंट रेट से अधिक दाम

श्रीगंगानगर. शहर में शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक दामों की वसूली आबकारी विभाग की कार्रवाई के बाद भी नहीं रुक नहीं पाई है। 'राजस्थान पत्रिका' की पड़ताल में सामने आया कि दुकानों पर कहीं बीयर पर तीन तो कहीं दस से पंद्रह रुपए वसूली हो रही थी।

अलवर : 5 से 15 रुपए महंगी बेच रहे

अलवर. अलवर शहर सहित जिलेभर में शराब ठेकों पर अधिकतम मूल्य से ज्यादा पर शराब बिक रही है। पत्रिका ने शनिवार को ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित और मनुमार्ग तिराहा स्थित दुकान पर स्टिंग किया।

जोधपुर : इसलिए बेच रहे हैं महंगी

जोधपुर. शहर में शराब व बीयर पर दस से बीस प्रतिशत तक की रेट ज्यादा ली जा रही है। शराब के ठेकों पर काम करने वाले सैल्समैन का कहना है कि आगे से माल की सप्लाई कम आ रही है। इसलिए ज्यादा रेट लेने को कहा गया है।

भीलवाड़ा : हर दुकान की अपनी रेट

भीलवाडा. भीलवाड़ा में हर दुकान संचालक ने अपनी अलग रेट निर्धारित कर रखी है। हर बोतल पर 50 से 100 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे थे। ग्राहक के ओवररेट लेने पर आपत्ति जताने पर सेल्समेन और उसके साथी झगड़े तक पर उतारू हो गए।

डूंगरपुर : रेट लिस्ट नहीं, मनमानी वसूली

डूंगरपुर. यहां शराब और बीयर हर ब्राण्ड पर 10 से लेकर 30 रुपए अधिक कीमत वसूली जा रही है। दुकानों पर रेट लिस्ट तक प्रदर्शित नहीं कर रखी। ग्राहक की ओर से अंकित मूल्य का हवाला दिया जाए तो सेल्समैन उसे टरका देते हैं।

अजमेर : पीनी है तो लो., दाम यहीं लगेंगे

अजमेर. वैशाली नगर स्थित एक मिष्ठान भंडार के पीछे स्थित दुकान पर पत्रिका टीम ने बियर की रेट पूछी। यहां 86 रुपए प्रिन्ट वाली बीयर की कैन के 100 रुपए, 126 प्रिन्ट के अंग्रेजी शराब के क्वार्टर के 130 रुपए और 172 के प्रिन्ट वाले क्वार्टर के 190 रुपए बताए। सेल्समेन ने बताया कि बियर ठंडी है और ऐसे में रेट भी ज्यादा लगेगी।

प्रतापगढ़ : खुले नहीं है, इसलिए राउंड फिगर में

प्रतापगढ़. जिले में शराब की रेट राउंड फिगर में ली जा रही है। पत्रिका टीम ने एक दुकान पर स्टिंग किया तो पता चला इम्पेरियल ब्लू अंग्रेजी शराब के प्रिंट रेट 404 रुपए थे, इसके 410 बताए। वहीं बीयर की एक बोतल पर 97 रुपए अंकित थे, जिसके सौ रुपए बताए। दुकानदार ने कहा, खुले नहीं मिलने से राउंड फिगर में राशि लेते हैं।

चित्तौड़गढ़ : 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से बिक्री

चित्तौडगढ़. पत्रिका ने शहर प्रमुख शराब के ठेकों का स्टिंग किया तो सामने आया कि शराब पर तय कीमत से लगभग 6 से 20 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। शराब बिक्री के बंद होने के बाद भी कई जगह शराब बेचे जा रही है। रात आठ बजे बाद भी शराब पर 20 से 50 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे है।

पाली : दस से बीस प्रतिशत ज्यादा रेट

पाली. आबकारी विभाग की मिलीभगत के कारण शराब ठेकों पर लूट जारी है। हर ठेकों पर शराब व बीयर के 10 से 20 प्रतिशत तक दाम ज्यादा लिए जा रहे हैं। शनिवार को पत्रिका संवाददाता ने मंडिया रोड स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके पर स्टिंग किया तो सैल्समैन यह कबूल कर रहा है कि ठेकेदार के कहने पर अंकित मूल्य से ज्यादा रेट शराब व बीयर की ली जा रही है।

नागौर : खुद ही तय कर ली कीमतें

नागौर. जिले के कुचामण में शराब विक्रेताओं ने खुद ही निर्धारित कर ली शराब की दरें। इसके लिए बाकायदा मीटिंग रखकर लिखित में निर्णय लिया गया और सभी शराब विक्रेताओं ने हस्ताक्षर भी किये। शराब की दरें भी निर्धारित दरों से 10 फीसदी से अधिक की गई है। निर्णय यह भी लिया कि सरकारी रेट लेने पर 21 हजार का जुर्माना भी लगेगा।

राजस्थान पत्रिका द्वारा चलायी गयी मुहीम

कुछ दिन रोक लें ओवररेट वसूली, ठेकेदारों को पहुंचे संदेश

05/06/18 RP

आबकारी कार्यालयों से किए गए फोन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

जयपुर. चुनावी साल में 'वसूली' को लेकर अंग्रेजी शराब-बीयर बिक्री ओवररेट पर कराने का शुरू हुआ 'खेल' राजस्थान पत्रिका के खुलासे के बाद कुछ दिन थामने के लिए कहा जा रहा है। आबकारी अधिकारियों की शह पर ही हर जिले में ठेकेदारों की यूनियन बनाकर शुरू कराए गए इस खेल को लेकर अब शराब ठेकेदारों को फोन कर संदेश दिया गया है कि कुछ दिन के लिए ओवररेट वसूली रोक दी जाए। सूत्र बताते है कि पिछले दो दिन से आबकारी कार्यालयों से ठेकेदारों को फोन पहुंच रहे है। कहा जा रहा है कि पुनः ओवररेट वसूली शुरू करने को लेकर बाद में सूचना दी जाएगी। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में आबकारी कार्यालयों से गत दो दिनों में शराब ठेकेदारों को फोन कराए गए है। अधिकांश जिलों में फोन पर यहीं संदेश दिया जा रहा है कि अगली सूचना मिलने तक ओवररेट नहीं वसूली नहीं करनी है। इस संदेश के बाद कुछ ठेकेदार पुरानी रेट पर ही कारोबार करने लगे है, वहीं कई मोटी कमाई के चक्कर में अब भी ओवररेट पर शराब बेच रहे है।

फॉलोअप

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर।

3 माह से आयुक्त का पद रिक्त

आबकारी विभाग में आयुक्त का पद तीन माह से अधिक समय से रिक्त है। 28 फरवरी को आयुक्त ओ.पी. यादव के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद का अतिरिक्त कार्यभार उदयपुर के संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा को सौंपा गया था। लेकिन दूसरे दिन ही नया आदेश जारी कर इस पद की जिम्मेदारी वित्त विभाग के सचिव प्रवीण गुप्ता को सौंप दी गई। उसके बाद से इस पद का काम गुप्ता ही देख रहे हैं। उधर, जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में अधिकारी ऊंची पहुंच के चलते चार साल से भी अधिक समय से एक ही पद पर जमे हैं।

नियम का हो रहा उल्लंघन

शराब बिक्री को प्रोत्साहन नही देने को लेकर सरकार के स्तर पर कई बार वादे किए जा चुके हैं। दुकान के आसपास प्रचार नहीं किया जा सकता। होर्डिंग्स भी निर्धारित आकार का सिर्फ लाइसेंसी के नाम का लगाया जा सकता है। लेकिन इनका तो उल्लंघन हो ही रहा है, अब तो शराब ठेकेदारों ने ग्राहकों को खींचने के लिए अतिरिक्त स्टाफ रखना शुरू कर दिया है। यह प्रचार की श्रेणी में आता है।

सरकार की मेहरबानी से ओवररेटः कांग्रेस

जयपुर. कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर शराब ठेकेदारों द्वारा एमआरपी की बजाय मनमानी कीमत वसूल करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एवं जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि इस तरह 100 करोड़ से अधिक रुपए जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। एमआरपी से अधिक पर शराब की कीमत वसूलने का अधिकार नहीं है।

शराब माफिया के खिलाफ आम जन

ओवररेट के नाम पर इस संगठित अपराध से हर शराब का सेवन करने वाला त्रस्त है और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही चाहता है|इसी लिए हमारे द्वारा एक **" Public Against Liquor Mafia "** नामक अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमे आम जन का सहयोग अपेक्षित है|

आपको क्या करना है?

शराब की अधिक कीमत वसूलने पर ठेकेदार का वीडियो बनाये और हमें भेजे|

आबकारी विभाग द्वारा ओवररेट के मामलों में की जाने वाली लीपापोती जगजाहिर है,विभाग ऐसे मामलों में कार्यवाही करे इसके लिए आवश्यक है कि आम जन ऐसे दुकानदारों की वीडियो रिकॉर्डिंग बना कर हमें भेजे ताकि विभाग को यह वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की जा सके और उचित कार्यवाही के लिए सरकार पर जनता का दबाव बनाया जा सके|